वर्षाऋतु के कारण पानी जमा हो जाने के परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त हालत में है। इसलिए प्रयोगशाला को बिहार सरकार द्वारा पर्याप्त उपकरण और विशेषज्ञ जांच कार्मिक मुहैया नहीं कराए गए हैं।

(घ) बिहार सरकार से प्रयोगशाला को पुनः शुरू करने के लिए भवन के ढांचे में सुधार करने अथवा अपेक्षित उपकरण और कार्मिक शक्ति मुहैया करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

राज्य सरकार की औषध जांच प्रयोगशालाओं और केन्द्रीय सरकारी औषध जांच प्रयोगशालाओं के राज्यवार नाम, संख्या और वे कहां कहां स्थित हैं;

राज्य का नाम	केन्द्रीय प्रयोगशाला	राज्य प्रयोगशाला
आंध्र प्रदेश		हैदराबाद
		विजयवाड़ा
असम	गुवाहाटी	
बिहार		पटना
दिल्ली		दिल्ली
गुजरात		वदोदरा
गोवा		पणजी
हिमाचल प्रदेश		शिमला
हरियाणा		चंडीगढ़
जम्मू व कश्मीर		जम्मू
		श्रीनगर
केरल		तिरूवनंतपुरम
कर्नाटक		बेंगलूर
महाराष्ट्र	मुम्बई	मुम्बई
उड़ीसा		भुवनेश्वर
पंजाब		चंडीगढ़
राजस्थान		जयपुर
तमिलनाडु	चेन्नई	चेन्नई
उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	लखनऊ
पश्चिमी बंगाल	कलकत्ता	कलकत्ता

Rationalisation of Medical Services Suggested by AIIMS

974. SHRI SANJAY DALMIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the All India Institute of Medical Sciences has suggested rationalisation of medical services in the country and to adopt a three-tier system for providing medical facilities to the people at the village and district levels;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have examined the suggestions made by the AIIMS; and

(d) if so, the steps being taken by Government to implement those suggestions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): (a) to (d) The three-tier system of rural health infrastructure in the village level has been adopted from the 5th Five Year Plan onwards. The system comprises of Sub-centres, Primary Health Centres and Community Health Centres established on the basis of population norms. The services provided by the infrastructure include preventive, promotive and curative health care to the people dwelling in the area. The All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) has not made any specific suggestion in this regard.

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की अपर्याप्तता

975. **श्री एस०एस० सुरजेवाला:**
श्री अजीत जोगी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों में औषधियों की अनुपलब्धता, अपर्याप्त प्रसव सुविधाओं और डाक्टरों/चिकित्सा अधिकारियों की कमी के संबंध में हाल ही में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधाओं की कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमों में सुधार लाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) और (ख) वर्ष 1993 में सामाजिक सुरक्षा नेट योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के 32 जिलों, मध्य प्रदेश व राजस्थान के 23-23 जिलों, बिहार के 5 जिलों, पश्चिम बंगाल और गुजरात के 2-2 जिलों तथा हरियाणा, केरल व उड़ीसा के 1-1 जिलों को कवर करते हुए 90 जनांकिकीय तौर पर कम निष्पादन वाले जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर सुविधा सर्वेक्षण किया गया था।

सर्वेक्षण किए गए 3405 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से केवल 15% में प्रसव कक्ष और 13% ऑपरेशन थिएटर थे। केवल 18% प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा प्रसवें करवाने की सूचना मिली है और 19% प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कोई चिकित्सा अधिकारी नहीं था।

(ग) कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं का मुख्य कारण प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या स्कीमों का कम वित्त पोषण था जिसके परिणामस्वरूप आधारभूत ढांचे की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य के लिए चिकित्सा व परा-चिकित्सा स्टाफ की अनिच्छा और औषधों व उपस्करों की कमी है।

(घ) राज्य का विषय होने के कारण केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को कहा कि वे देखें कि औषधों, उपस्करों तथा अनिवार्य रखरखाव के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित की जाएं। राज्य को समय-समय पर सलाह दी जाती है कि चिकित्सा व परा-चिकित्सा स्टाफ की मौजूदा रिक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए। उपर्युक्त के अतिरिक्त विभिन्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत देश में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है।

Exhorbitant Charges of Private Nursing Homes in Delhi

976. SHRI AMAR SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of private nursing homes functioning in the Union Territory of Delhi;

(b) whether Government are aware that private nursing homes are charging exhorbitant charges from patients and if so, what is Government's reaction in regard thereto;

(c) whether Government's attention has been drawn to the recent incident of Dewan Nursing Home, Sarai Rohilla, Delhi which charged Rs. 2200/- from the father of a child for three stitches on the chin, which appeared in "Pioneer" dated the 25th June, 1997; and

(d) if so, what action has been taken against the said Nursing Home?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): (a) Government of National Capital Territory of Delhi have reported that 596 private Nursing Homes are functioning in Delhi.

(b) There is no provision of fixing rates for various services rendered by private Nursing Homes in Delhi under Delhi Nursing Home Registration Act, 1953. However, the registered Nursing Homes in Delhi are required to display the schedule of charges.

(c) and (d) Yes, Sir. However, as per the investigation conducted by the Government of NCT of Delhi, the Dewan Nursing Home had raised a bill of Rs. 650/- which was further reduced to Rs. 300/- only. This amount is yet to be paid to the Nursing Home.

World Bank Aided Health Projects in Tamil Nadu

977. SHRI N. THALAVAI SUNDARAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Tamil Nadu Government has taken up health projects with the assistance of World Bank; and

(b) the extent to which each of the said projects has been successful?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): (a) and (b) As per information available with the Government a World Bank assisted India Population Project was taken up in